लिए प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उत्पादों हेतु औद्योगिक नीति उदार बनाने और अनिवार्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा सरकार ने विभिन्न योजना स्कीमें भी तैयार की हैं। आधारभूत सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यद्यपि आठवीं योजना के दौरान फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं परन्तु फल एवं सब्जी उद्योगों की संस्थापित क्षमता 9.5 लाख टन से बढ़कर 20 लाख टन प्रतिवर्ष होने की आशा की जाती है।

आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा निपटाये गए मामले

2613. श्री राजूभाई ए० परमार : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान आयकर सम्बन्धी लम्बित मामलों का शीघ्र निपटान करने हेतु आयकर अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को कहां-कहां भेजा गया था; और

(ख) उन्होंने दौरों पर जाकर कितने मामलों का निपटान किया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) आय-कर अपील अधिकरण के सदस्यों को पिछले दो वर्षों के दौरान दौरे पर निम्नलिखित स्थानों पर भेजा गया था :-

मुंबई, नागपुर, पुणे, मद्रास, कोचीन, बंगलौर, कलकत्ता, पटना, कटक, इलाहाबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, इन्दौर, जबलपुर, अमृतसर, नासिक, बेलगांव, कानपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ और रांची।

(ख) दौरों की इस अवधि के दौरान आय-कर अपील अधिकरण के सदस्यों ने 8818 मामले निपटाए।

दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की खण्ड पीठ

2614. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की एक खण्ड पीठ स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा, जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Companies Promoted by Harshad Mehta

2615. SHRI SUSHIL. KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of the companies promoted by Shri Harshad Mehta and his family members with their dates of incorporation;

(b) whether these companies submitted' their annual reports audited profit and loss accounts and balance sheets since their incorporation; and

(c) names of the auditors of the above mentioned companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) to (c) *A* satement to ansexed.

Statement

SI. No.	Names of the companies promoted by Shri Harshad Mehta and his family members	Date of incorpo-ration	Last audit-ted Balance Sheet and Profit & Loss ac-count filed with Regis trar of	Names of Auditors
1	Growmore Research & Assests Management Ltd.	24-4-87	31-3-90	Kiran Kapadia & Co., Chartered Ac-countants, Bombay
2	Aatur Holding Pvt. Ltd.	9-6-87	31-3-90	Do.
3	Harsh Estates Pvt. Ltd.	9-6-87	31-3-90	Do.
4	Growmore Exports Pvt. Ltd.	. 24-2-89	31-3-90	Do.
5	Griowmore Leasing & Investments Ltd	. 24-2-89	31-3-90	Do.
6	Orion Travels Pvt. Ltd.	26-2-90	31-3-90	Do.
7	Fortune Holdings Pvt. Ltd. .	. 2-3-90	31-3-90	Do.
8	Cascade Holdings Pvt. Ltd. .	. 2-3-90	31-3-90	Do.
9	Treasure Holdings Pvt Ltd.	. 25-10-91	Nil (not due)	First Balance Sheet not yet due for filing. In the ab-sence of the Balance Sheet, the name(s) of the Auditor(s)
10	Velvet Holdings Pvt. Ltd. .	. 30-10-91		Do
11	Eminent Holdings Pvt. Ltd. .	. 30-10-91		Do.
12	Pallavi Holdings Pvt. Ltd. .	. 30-10-91		Do.
13	Zest Holdings Pvt. Ltd.	. 30-10-91		Do.
14	Topaz Holdings Pvt. Ltd. .	. 30-10-91		Do
15	Divine Holdings Pvt. Ltd.	. 30-10-91		Do.

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2616. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में न्याया-धीशों के कुल कितने पद हैं;

(ख) इस समय कितने पद रिक्त हैं; और कब से रिक्त हैं;

(ग) सरकार इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(घ) कार्यरत न्यायाधीशों में कितने न्यायाधीशों को 'बार' से नियुक्त किया गया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) से (घ) तारीख 30.7.92 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृत संख्या 26 थी । 25 न्यायाधीश